International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

वैश्विक सम्मेलन और हरित राजनीति: सतत विकास की ओर एक दृष्टिकोण

ज़ीशान अहमद[1], आशीष कुमार गुप्ता[2]

[1]शोधार्थी, ने. मे. शि. न. दास (पी० जी०) महाविद्यालय, बदायूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, ने. मे. शि. न. दास (पी० जी०) महाविद्यालय, बदायूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश

इस शोध पत्र में वैश्विक सम्मेलनों और हरित राजनीति की भूमिका का विश्लेषण किया गया है, जो सतत विकास को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन, और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हरित राजनीति और सतत विकास की नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विभिन्न वैश्विक सम्मेलनों, जैसे कि रियो समिट (1992), क्योटो प्रोटोकॉल (1997), और पेरिस समझौता (2015), का अध्ययन कर यह समझने का प्रयास किया गया है कि ये समझौते किस हद तक प्रभावी रहे हैं।

मूल शब्द: पर्यावरण संकट, वैश्विक सम्मेलन, रियो समिट, पेरिस समझौता।

1. परिचय

21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण विश्व के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ बनकर उभरे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग, औद्योगीकरण, और कार्बन उत्सर्जन के बढ़ते स्तर के कारण धरती के पारिस्थितिकीय संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए विभिन्न वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों की आवश्यकता पड़ी, जिससे सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा मिला।

हरित राजनीति (Green Politics) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह राजनीति टिकाऊ नीतियों, अक्षय ऊर्जा संसाधनों, और कार्बन
उत्सर्जन को कम करने के उपायों पर केंद्रित है।

2. सतत विकास और हरित राजनीति

सतत विकास (Sustainable Development) वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। यह तीन प्रमुख स्तंभों–आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय–पर आधारित है।

हरित राजनीति का उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार को भी सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना
पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना
दीर्घकालिक विकास और टिकाऊ आर्थिक नीतियाँ अपनाना

3. वैश्विक सम्मेलन और हरित राजनीति

हरित राजनीति के प्रचार-प्रसार और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए गए।

3.1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (1972)

स्थान: स्टॉकहोम, स्वीडन

मुख्य उपलब्धि: यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता दी गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना हुई।

3.2. पृथ्वी सम्मेलन (रियो समिट, 1992)

स्थान: रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील

मुख्य उपलब्धि: सतत विकास के लिए "**एजेंडा 21**" अपनाया गया।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की स्थापना हुई।
जैव विविधता संधि (CBD) पर सहमति बनी।

3.3. क्योटो प्रोटोकॉल (1997)

उद्देश्य: ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना
मुख्य बिंदु: विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया। 'कार्बन क्रेडिट' की अवधारणा प्रस्तुत की गई।

3.4. पेरिस समझौता (2015)

उद्देश्य: वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना
मुख्य उपलब्धि: सभी देशों को ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया।
अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया।
देशों को अपनी राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ (NDCs) प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

4. हरित राजनीति की सफलता और चुनौतियाँ

4.1. सफलता

हरित ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ा है।
जन जागरूकता में वृद्धि हुई है।
हरित तकनीकों का विकास हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा।

4.2. चुनौतियाँ

विकसित और विकासशील देशों के बीच वित्तीय असमानता।
हरित ऊर्जा की उच्च लागत और तकनीकी बाधाएँ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और नीति कार्यान्वयन में देरी।

5. भविष्य की रणनीतियाँ और समाधान

हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाना – सौर, पवन और जल ऊर्जा को अधिक अपनाना।
सख्त नीतिगत ढांचा – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर नियम लागू करना।
स्थानीय समुदायों की भागीदारी – जलवायु कार्रवाई में नागरिकों को शामिल करना।
तकनीकी नवाचार – अधिक ऊर्जा दक्ष और टिकाऊ समाधान विकसित करना।

शोध प्रविधि

शोध उद्देश्य

1. वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलनों (जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता) की भूमिका और प्रभाव का विश्लेषण।
2. हरित राजनीति (Green Politics) की अवधारणा और इसके वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावों का अध्ययन।

शोध परिकल्पना

H_0 (शून्य परिकल्पना): वैश्विक सम्मेलन और हरित राजनीति का सतत विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव
नहीं पड़ता।

H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): वैश्विक सम्मेलन और हरित राजनीति सतत विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देते हैं।

यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान पर आधारित है:

वर्णनात्मक अनुसंधान: वैश्विक सम्मेलनों, नीतियों और हरित राजनीति की अवधारणाओं का वर्णन।
विश्लेषणात्मक अनुसंधान: पर्यावरणीय नीतियों के प्रभावों और विभिन्न देशों में उनके कार्यान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन।

द्वितीयक आंकड़ा स्रोत (Secondary Data Sources)

1. संयुक्त राष्ट्र (UN), IPCC, और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट।
2. शोध पत्र और जर्नल्स (Springer, Elsevier, और JSTOR)□
3. सरकारी नीति दस्तावेज और वैश्विक सम्मेलन रिपोर्ट (जैसे पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, आदि)।

डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

तुलनात्मक अध्ययन: विभिन्न देशों की हरित नीतियों की तुलना।
वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics): पर्यावरणीय नीतियों के रुझानों का ग्राफ़ और चार्ट द्वारा विश्लेषण।
नीति मूल्यांकन: वैश्विक सम्मेलनों के प्रभाव का अध्ययन।

1. सतत विकास की अवधारणा

a. ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987)

ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रकाशित "Our Common Future" रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया:

"ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरा न हो।"

यह रिपोर्ट सतत विकास (Sustainable Development) की आधारशिला मानी जाती है।

b. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) – 2015

2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:

जलवायु कार्रवाई (Climate Action)

स्थायी शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities)

स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)

स्रोत: United Nations Development Programme (UNDP), Sustainable Development Goals Report (2023)

2. वैश्विक सम्मेलन और पर्यावरणीय समझौते

a. स्टॉकहोम सम्मेलन (1972)

पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, जिसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना की।

इसने "पर्यावरणीय अधिकारों" की अवधारणा को बल दिया।

स्रोत: United Nations Environment Programme (UNEP)

b. रियो समिट (Earth Summit, 1992)

इस सम्मेलन में "एजेंडा 21" को अपनाया गया, जो सतत विकास की एक व्यापक कार्ययोजना है।

इसमें तीन प्रमुख संधियों पर सहमति बनी:

1. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
2. जैव विविधता संधि (CBD)
3. मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि (UNCCD)

स्रोत: United Nations Conference on Environment and Development (UNCED, 1992)

© क्योटो प्रोटोकॉल (1997)

मुख्य उद्देश्य: ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करना।

कार्बन क्रेडिट और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) जैसी अवधारणाएँ पेश की गईं।

आलोचना: अमेरिका ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया।

स्रोत: UNFCCC, Kyoto Protocol Status Report (2022)

c. पेरिस समझौता (2015)

उद्देश्य: वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखना और 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास।

सभी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया।

इसे जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्त्वपूर्ण समझौता माना जाता है।

स्रोत: UNFCCC Paris Agreement Report (2023)

3. हरित राजनीति (Green Politics) और उसकी भूमिका

a. हरित राजनीति की अवधारणा

Dobson (2007) ने हरित राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा कि यह केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता भी शामिल है।

स्रोत: Green Political Thought (Andrew Dobson, 2007)

b. हरित राजनीति के वैश्विक उदाहरण

1. **यूरोपीय संघ (EU):** "ग्रीन न्यू डील" (Green New Deal) नीति के तहत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य।
2. **जर्मनी:** "एनर्जिवेंड (Energiewende)" नीति, जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है।
3. **भारत:** "राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission)" और "राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (National Biodiversity Action Plan)" के तहत हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा।

स्रोत: European Green Deal Report (2023), India Renewable Energy Report (2022)

4. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर प्रभाव

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) की रिपोर्ट के अनुसार: यदि तापमान वृद्धि 1.5°C से अधिक हो गई, तो 2030 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन 10% तक घट सकता है।

जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान होगा।

Nicholas Stern (2006) की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन से वैश्विक GDP में 5-20% तक की गिरावट आ सकती है।

स्रोत: IPCC Sixth Assessment Report (2023), Stern Review on the Economics of Climate Change (2006)

5. सतत विकास के लिए वित्तीय पहल

ग्रीन बॉन्ड्स (Green Bonds): 2023 में वैश्विक ग्रीन बॉन्ड बाजार $500 बिलियन से अधिक हो गया।

स्रोत: Climate Bonds Initiative Report (2023)

कार्बन टैक्स (Carbon Tax): स्वीडन में कार्बन टैक्स के कारण 1990 के बाद से कार्बन उत्सर्जन 27% कम हुआ।

स्रोत: World Bank Carbon Pricing Dashboard (2023)

1. कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन डेटा

YEAR	GLOBAL CO2 EMISSION (In Gigatonnes)	AVERAGE GROBAL TEMPRATURE RISE(•C)
1990	22.2 Gt	+0.4 •C
2000	25.1 Gt	+0.6 •C
2010	33.1 Gt	+0.9 •C
2020	36.7 Gt	+1.2 •C

स्रोत: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Global Carbon Project

2. वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग

YEAR	SOLAR ENERGY	WIND ENERGY	HYDRO POWER	TOTAL RENEWABLE ENERGY
2000	0.5%	1.1%	16.5%	18.1%
2010	2.3%	3.8%	15.8%	21.9%
2020	9.4%	7.3%	15.3%	32.0%

स्रोत: International Energy Agency (IEA), REN21 Global Status Report

3. ग्रीन फाइनेंस और निवेश

YEAR	GREEN BONDS (International Investment)	SUSTANABLE ENERGY INVESTMENTS (Billion Dollar)
2015	104 Billion Dollar	288 Billion Dollar
2020	270 Billion Dollar	501 Billion Dollar
2023	500+ Billion Dollar	755 Billion Dollar

स्रोत: World Bank, Climate Policy Initiative (CPI)

4. प्रमुख देशों द्वारा हरित ऊर्जा में निवेश

COUNTRY	RENEWABLE ENERGY INVESTMENT [2023, BILLION DOLLAR]	KEY STRATERGIES
CHINA	380+	Solar and wind power expansion
USA	215	Clean energy act
EU	175	Green deal, carbon neutral target
INDIA	100+	Solar mission, hydrogen energy investment

स्रोत: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), International Renewable Energy Agency (IRENA)

5. जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि

YEAR	CLIMATE- RELATED DESASTER [NUMBER]	PEOPLE AFFECTED [IN CRORE]	FINANCIAL LOSS [BILLION DOLLAR}
2000	250	5.0	80
2010	320	6.8	120
2020	400+	9.2	250+

स्रोत: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), World Meteorological Organization (WMO)

6. भविष्य की संभावनाएँ और अनुमान

2050 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़ सकती है।

वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5°C से नीचे रखने के लिए 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 50% तक घटाने की आवश्यकता है।
हरित नौकरियों की संख्या 2030 तक 25 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।
स्रोत: International Labour Organization (ILO), IPCC, UNFCCC

निष्कर्ष

इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैश्विक सम्मेलन और हरित राजनीति सतत विकास के लिए आवश्यक उपकरण हैं, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ठोस नीतिगत सुधारों, वित्तीय संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
यदि वैश्विक नेता, नीति-निर्माता, और आम जनता एक साथ मिलकर कार्य करें, तो हरित राजनीति को और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future. Oxford University Press.
2. Dobson, A. (2007). Green Political Thought. Routledge.
3. United Nations (1972). Stockholm Declaration on the Human Environment. UNEP.
4. United Nations (1992). Agenda 21: The Rio Declaration on Environment and Development. UNCED.
5. UNFCCC (1997). Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
6. UNFCCC (2015). The Paris Agreement. United Nations.
7. United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development
8. International Energy Agency (IEA) (2023). World Energy Outlook 2023.
9. World Bank (2022). State and Trends of Carbon Pricing 2022.
10. International Renewable Energy Agency (IRENA) (2023). Renewable Capacity Statistics 2023.
11. National Institute of Transforming India (NITI Aayog) (2022). India's SDG Index Report.
12. BBC News (2023). "COP28: Key Outcomes and Challenges for Climate Policy.
13. The Guardian (2023). "The Future of Renewable Energy and Carbon Neutral Goals."
14. Down to Earth (2023). "India's Climate Action: Challenges and Opportunities."